

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री आई0 एस0 सिद्दीकी  
मे0 एलिडको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रिज लि0,  
एलिडको कॉरपोरेट चैम्बर-1, 2 फ्लोर,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010

संदर्भ संख्या 1083/1051/यूपीसीडा/परि0का0/2025-26

दिनांक 24/12/2025

विषय:- अनुज्ञा पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा प्राधिकरण के अनुज्ञा पत्र संख्या-2095 दिनांक 16.03.2021 इम्पीरिया फेज-1 ग्राम जैतीखेड़ा, परगना-बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, जिला लखनऊ कुल क्षेत्रफल 6.878 हे0 पर भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृत किया गया। स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र में आप द्वारा शॉपिंग फेज-1 कुल क्षेत्रफल 1963.80 वर्गमीटर मानचित्र स्वीकृत किए जाने हेतु दिनांक 20.08.2025 को ऑनलाइन ई-सर्विस पोर्टल पर आवेदन किया गया। तत्क्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जा रही है :-

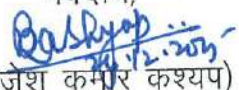
1. यह स्वीकृति पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि निर्माण आज्ञानुकूल नहीं हुआ तो लीडा द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा यदि कोई निर्माण बिना यूपीसीडा एक्स-लीडा की अनुमति प्राप्ति किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उनके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय निर्माण को यूपीसीडा एक्स-लीडा द्वारा हटवाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार निर्माण बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।
2. इस अनुमति पत्र के सड़क या गली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे पोर्टिकों बारजा, तोड़ा सीटी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर नये निर्माण की स्वीकृति चाहें उसके साथ नक्शों में दिखाई भी गयी हो, नही प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिये प्राधिकरण सुसंगत अधिनियम की धारा के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. निर्माण से यदि नाली की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग को निर्माण के आगे-पीछे अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो निर्माण के आगे अथवा पिछे उसके आकार के कारण लटकाई गई हो) हानि पहुँचे तो यह निर्माण स्वामी को छत तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा तो उसे पहले ही तोड़कर अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में, जिससे प्राधिकरण को संतोष हो जावे, में कर देना होगा।
4. निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिये। यदि यूपीसीडा (एक्स-लीडा) की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार लीडा को निर्माण के पूर्ण हो जाने की सूचना निर्माण समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अन्दर देना होगा।
6. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध नहीं मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्माण आदि हटाये जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इस लिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण को प्रारम्भ करें।
7. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना यूपीसीडा (एक्स-लीडा) को देनी होगी।
8. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजी० व आर्की० की देखरेख में निर्माण कार्य कराया जायेगा। विशिष्टियों/गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये यूपीसीडा (एक्स-लीडा) जिम्मेदार नहीं होगा।
9. आवेदक का मानचित्र जिस उपयोग हेतु निर्धारित अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है उस अवधि में कार्य पूर्ण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना अनिवार्य है।
10. प्राधिकरण के सहा० प्रबन्धक परि० द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।
11. प्राधिकरण की भवन नियमावली एवं अन्य शर्तें आवेदक को मान्य होगी।
12. किसी भी नियमों की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।
13. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय-2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।
14. निर्माण के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।
15. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरिकृत ड्राइंग या समकक्ष फार्मेट में) सी०डी० में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त जारी किया जायेगा।
16. इस अनुज्ञा से संदर्भित भू/गृह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधिवत् कार्यवाही हेतु निरायोग्य अथवा/विधिवत् करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
17. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छल पूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्त की जा सकती है।
18. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आरकेड वालकनी, छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहें भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी।
19. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें, अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें, जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।
20. भू-स्वामित्व के संबंध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। इस प्रकार अनुज्ञा से संदर्भित भू/गृह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधिवत् कार्यवाही हेतु निरायोग्य अथवा/विधिवत् करती है एवं

इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भौति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

21. मानचित्र में दर्शित अशमनीय निर्माण यदि निर्धारित तिथि तक पक्ष द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का प्रतिशत हर्जाना कार्यवाही करके पक्ष से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल करेगा।
22. आवश्यक समस्त शासकीय अनापत्ति आप द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
23. सीवर व अन्य आवश्यक डिस्पोजल की व्यवस्था आप द्वारा स्वयं की जायेगी।
24. भविष्य में यदि भवन अनुज्ञा शुल्क या लेबर सेस शुल्क के सम्बन्ध में कोई देयता होती है तो आवेदनकर्ता को सम्बन्धित विभाग में जमा कर उसकी सूचना प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी।
25. प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कराना होगा व स्वीकृति के उपरान्त यदि आवेदक द्वारा मानचित्र में दर्शित क्षेत्रफल से अधिक निर्माण कराया जाता है तो निर्माण से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक/कम्पनी की होगी।
26. परियोजना के साथ लगी महायोजना सड़क के समान्तर यदि हरित पट्टी का प्राविधान होता है तो उक्त प्राविधान के अनुरूप परियोजना में समायोजित किया जाना अनिवार्य होगा।
27. आवेदक संस्था द्वारा यदि अपने पक्ष में लीज़ डीड की अवधि नहीं बढ़ायी जाती है तो मानचित्र की वैधता अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित दिनांक को समाप्त हो जायेगी।
28. आवेदक संस्था को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क/बाह्य विकास शुल्क में प्रदान की गयी छूट को नोडल एजेन्सी/शासन द्वारा अन्तिम रूप से अनुमन्य करने पर ही मान्य होगा अन्यथा की दशा में छूट प्रदान की गयी शुल्क की समस्त धनराशि आवेदक संस्था वसूल कर ली जायेगी। यदि शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि होती है तो आवेदक संस्था को शुल्क प्राधिकरण के पक्ष में भुगतान करना होगा।
29. भू-विन्यास मानचित्र पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व थर्ड पार्टी (आई.आई.टी/आई.ई.टी) अथवा सरकारी समकक्ष संस्थान से निरीक्षण के उपरान्त ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
30. यह स्वीकृत भवन मानचित्र हेतु है तथा इससे भू-स्वामित्व सिद्ध नहीं होता है।
31. उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत भवन मानचित्र का एक सेट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, परियोजना का निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

भवदीय,  
  
(बृजेश कुमार कश्यप)  
प्रभारी परियोजना अधिकारी

संदर्भ संख्या / 1051 / यूपीसीडा / परि०का० / 2025-26

दिनांक

प्रतिलिपि :-अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी०) महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(बृजेश कुमार कश्यप)  
प्रभारी परियोजना अधिकारी



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (लेसा-सिस गोमती)  
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बंगला बाजार प्रथम तल,  
सिस-गोमती, लेसा, लखनऊ।

पत्रांक : - मु0अ0/ले0सि0गो0/आ0वि0भा0/

दिनांक: 31/08/2021

**कार्यालय ज्ञापन**

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, घतुर्थ, लेसा सिस गोमती, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 1159/वि0वि0मं0(घ0)/ विद्युत भार, दिनांक 12.08.2021 द्वारा आवासीय अवस्थापना विद्युत भार बहुबिन्दु मीटरिंग प्रणाली पर स्वीकृति हेतु मय संस्तुति के साथ उपलब्ध कराये गये स्थलीय निरीक्षण/तकनीकी आख्या/भार संगणना एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-सेस प्रथम, ले0सि0गो0 के पत्रांक 2995/वि.वि. खं(सेस प्रथम)/लेसा-सिस गोमती दिनांक 09.08.2021 के आधार पर एतद्वारा निम्नलिखित इकाई/पार्टी के पक्ष में अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन (आवासीय अवस्थापना) बहुबिन्दु मीटरिंग विद्युत भार बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु स्वीकृत किया जाता है:-

क. सं.	इकाई/पार्टी का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	प्रयोजन	कार्यस्थल
1	2	3	4	5
1	श्री अजय कुमार श्रीवारस्तव पुत्र श्री कृष्ण मोहन श्रीवारस्तव, एल्डिको इम्पीरिया, जैती खेड़ा, परगना बिजनौर, सरोजनी नगर, लखनऊ।	1175 कि0वाँ0 (आवासीय अवस्थापना) बहुबिन्दु मीटरिंग	एल.एम.वी.-1	पता-खसरा सं0 30,31,32,33,34,35,36,37Ba, 37Sa,42,43,44,142Sa,142MI,149,150,151, 152,152MI,153,155,293Sa,293/2, ग्राम-जैती खेड़ा, परगना बिजनौर, सरोजनी नगर, लखनऊ।

उपरोक्त विद्युत भार विद्युत वितरण संहिता 2005 (संशोधित) एवं इससे सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत Amendments of Electrical Supply code में निहित प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त अवमुक्त किया जाये।

1. उपरोक्त विद्युत भार उ0प्र0 विद्युत सप्लाई कोड (13वां संशोधन) सं0-यू0पी0एस0आर0सी0/एस0ई0सी0आई0/ रेगुलेशन/सप्लाई कोड/2018/206 दिनांक 10.08.2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार बहु बिन्दु मीटरिंग के आधार पर निर्गत किया जायेगा।
2. उपरोक्त परिसर यदि लखनऊ विस्तारित सीमा के अन्तर्गत आता है, तो वह मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश MISC.BENCH.No. 218 to 2020 दिनांक 14.02.2020 सपवित सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्रांक 174/सचिव-प्रा0भ0/2020 दिनांक 06.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा (इन आदेशों की प्रतियाँ पूर्व में प्रेषित की जा चुकी हैं)।
3. पार्टी/इकाई द्वारा जब 1175 कि0वाँ0 विद्युत भार का सम्पूर्ण विद्युत तंत्र विकसित कर लिया जाए। तत्पश्चात् सभी वांछित NOC प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रथम विद्युत भार अवमुक्त किया जाए।
4. उपरोक्त विद्युत भार 11केवी जैती खेड़ा पोषक से उसका कुछ विद्युत भार उपभोक्ता के व्यय पर 33/11केवी विद्युत उपकेन्द्र अम्बेडकर विश्वविद्यालय उपकेन्द्र के 11केवी उत्तरेठिया पोषक पर 11केवी लाईन का निर्माण करके डालने के उपरान्त अवमुक्त किया जाय।
5. उक्त परियोजना यदि एल0डी0ए0 क्षेत्र में है तो यह स्वीकृति बिन्दु सं0 2 से नियंत्रित होगी अगर बिन्दु सं0 2 का पूर्णतः अनुपालन नहीं होता है तो स्वतः निरस्त समझी जाए।
6. परियोजना के विद्युत तंत्र का रखरखाव स्वयं RWA अपने व्यय पर करेगा।
7. विद्युत भार अवमुक्त करने हेतु कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत यथा-अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय की अनापत्ति प्रमाण पत्र के संतोषजनक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
9. वितरण परिवर्तकों के एल0वी0 साइड में परिवर्तक की क्षमता के 40 प्रतिशत क्षमता के अनुसार कैपिसिटर बैंक (ए0पी0एफ0सी0) स्थापित करना होगा।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा 11 के0वी0 वितरण नेटवर्क एवं एल0टी0 नेटवर्क का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि मूल पोषक के ब्रेक डाउन में आने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सके।
11. विद्युत प्रणाली की लोडिंग के कारण आपूर्ति विभव मानक से कम/अधिक हो सकती है। अतः कृपया 33/11 केवी के परिवर्तक पर आनलाईन टैप चेंजर जिसमें कम से कम 4टैप नार्मल टैप से ऊपर एवं 3टैप नार्मल टैप से नीचे हो, जिससे अधिकतम 13केवी तथा न्यूनतम 09केवी पर भी सुचारु रूप से मोटरे चल सके।
12. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/MVVNL/CIS-GOMTI,LESA के तकनीकी विशिष्टीकरण के अनुसार ही होनी चाहिए।

13. एनटीडी परिवर्तक उचित क्षमता का होना चाहिए।
14. डीएलएमएस/जीपीएस युक्त डबल मीटर सभी वितरण परिवर्तक पर इस्टाल होने चाहिए।
15. विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन में लागू रेट शिड्यूल में निहित बोल्टेज पर ही की जायेगी।
16. यदि भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण/उ०प्र० आवास विकास परिषद/नगर निगम/जिला पंचायत अथवा अन्य तत्सम्बन्धी सक्षम विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति की जाती है तो उस स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा। ऐसी स्थिति में स्वीकृत भार/संयोजन निरस्त कर दिया जाएगा।
17. प्रभावित 400/220/132 के०वी० उप-स्थानों पर स्थापित परिवर्तकों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जा सकती है।
18. विद्युत प्रणाली की लोडिंग के कारण आपूर्ति विभव मानक से कम/अधिक हो सकती है।
19. इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उक्त वर्णित विद्युत भार उपयोग न करने की दशा में अथवा नियम एवं शर्तें दिये जाने की तिथि से छह माह के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने की दशा में, जो भी तिथि पहले हो, से यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
20. उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के नियम के अन्तर्गत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली को सुरक्षा हेतु समय-समय पर आवश्यकता अनुसार रोस्ट्रिंग तथा आपातकालीन रोस्ट्रिंग की जा सकती है।
21. किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगर निगम/नगरपालिका/नगरमहापालिका/टाउन एरिया की सीमा से बाहर बढ़ाकर विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा। यदि कॉलम 6 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम से पहले से कोई कनेक्शन रहा हो, तो उक्त भार तब तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया धनराशि की प्रतिपूर्ति न कर ली जायें।
22. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और कारपोरेशन के मध्य कोई न्यायिक विवाद अथवा कोर्ट केस लम्बित हो तो इस दशा में भी विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
23. उक्त प्रकरण पर यदि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में इसका निस्तारण लखनऊ स्थित न्यायालय में किया जायेगा।
24. खण्डीय कार्यालय समस्त अभिलेखों की जांच अपने स्तर से करके तथा निर्धारित शुल्क जमा कराकर ही भार अवमुक्त करेगा।
25. उपरोक्त विद्युत भार इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया जाता है कि भार अवमुक्त करने के पूर्व सम्बन्धित खण्ड भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख आवेदनकर्ता से प्राप्त कर लें।
26. कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
27. विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, लखनऊ जोन, कमरा नं०-110 से विद्युत सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने के उपरान्त ही आप द्वारा विकसित प्रणाली तंत्र को सिस गोमती, लेसा नेटवर्क से जोड़ा जायेगा।
28. अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही भार अवमुक्त किया जाये।

कार्यालय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ जोन लखनऊ के कार्यालय से अधिष्ठापन का भारतीय विद्युत नियमावली, नियमों के अन्तर्गत सन्तोष-जनक प्रमाण पत्र प्राप्ति करें।

(मधुकर वर्मा)

मुख्य अभियन्ता (लेसा) सिस गोमती

संख्या : 1836/मु०अ०/लेसा-सिस गोमती/आ०वि०भा०/तददिनांक :- 31/08/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड-2, कमरा नं०.112 गोमती नगर, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-चतुर्थ, सिस गोमती, लेसा, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-सेस प्रथम, सिस-गोमती, लेसा, लखनऊ।
5. जिला पंचायत अधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
6. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, एल्लिको इम्पीरिया, जैती खेड़ा, परगना विजनौर, सरोजनी नगर, लखनऊ।

(मधुकर वर्मा)

मुख्य अभियन्ता (लेसा) सिस गोमती

# प्रारूप-घ (संलग्नक-3) औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/171093/LCK/LUCKNOW/8013/CFO

दिनांक: 06-09-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ELDECO HOUSING AND INDUSTRIES LIMITED** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **COMMERCIAL-01,,RESIDENTIAL TOWNSHIP ELDECO IMPERIA, JAITI KHERA,LUCKNOW** तहसील - **SAROJINI NAGAR** प्लॉट एरिया **1963.80 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2347.35** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
COMMERCIAL 01	3	0	12.39 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ELDECO HOUSING AND INDUSTRIES LIMITED** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Mercantile** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **ELDECO HOUSING AND INDUSTRIES LIMITED** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** प्रस्तावित भवन में N.B.C.-2016 (Part-4) मानक के अनुसार वांछित समस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रावधान करते हुये अधिभोग से पूर्व पूर्णता (कम्प्लीशन) अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**Note :** प्रस्तावित भवन में N.B.C.-2016 (Part-4) मानक के अनुसार वांछित समस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रावधान करते हुये अधिभोग से पूर्व पूर्णता (कम्प्लीशन) अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(ANKUSH MITTAL)

[C1A4F12653EE8617AC34BF4879D7820B631DA4C4]

08-09-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 08-09-2025  
स्थान : LUCKNOW

# State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow-226 010

Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543

E-mail : dneuplko@yahoo.com

Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Amit Kumar,  
M/s Eldeco housing & Industries Ltd,  
2<sup>nd</sup> Floor, Eldeco Corporate Chamber-1,  
Vibhuti Khnad, Gomti Ngar,  
Lucknow-226010

Ref. No. 132 /Parya/SEAC/4763/2019

Date: 28 June, 2019

Sub: Environmental Clearance for Residential Township at Khasra no- 30,31,32,33,34,35,36,37ba, 37sa, 42,43,44,142, 149, 150, 151, 152, 153,155, 293sa, 293sa, 148, 154, 62,146 & 147, Village-Jatikhera, Pargana-Bijnaur, Tehsil-Sarojni Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Eldeco Housing & Industries Ltd. Regarding.

Dear Sir,

Please refer to your application/letters 24-04-2019 & 25-04-2019 addressed to the Chairman/Secretary, State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and Director, Directorate of Environment Govt. of UP on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee considered the matter in its meetings held on dated 15/05/2019 and SEIAA in its meeting dated 11-06-2019.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s Ind Tech House Consult. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1. The environmental clearance is sought for Residential Township at Khasra no- 30,31,32,33,34,35,36,37ba, 37sa, 42,43,44,142, 149, 150, 151, 152, 153,155, 293sa, 293sa, 148, 154, 62,146 & 147, Village-Jatikhera, Pargana-Bijnaur, Tehsil-Sarojni Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Eldeco Housing & Industries Ltd.
2. Total plot area and built-up area of the project is 68,200 sqm and 47,077.09 sqm respectively. Saleable Plots are 150. Total No. of EWS & LIG Units is 32.
3. Estimated cost of the project is Rs. 50 Crores.
4. Salient features of the project:

S. No.	Description	Quantity	Unit
<b>GENERAL</b>			
1	Plot Area	68200	SQM
2	Area Under road widening	3433.127	SQM
3	Area under samaj land and chak road	2320.00	
4	Net Plot Area	62446.873	SQM
5	Proposed Built Up Area	47077.09	SQM
6	Total no of Residential Plots	150	NOS
7	No. of EWS & LIG Units (16 + 16)	32	NOS
8	Cost of Project	50	CR
9	Estimated Population of colony (1564 Residential- 482 Floating)	2046	PERSONS
<b>WATER</b>			
10	Total Water Requirement	188	KLD
11	Fresh Water requirement	109	KLD
12	Waste water Generation	133	KLD
13	Proposed STP capacity	160	KLD
14	Treated water available for Reuse	107	KLD
15	Recycled water	79	KLD
16	Surplus treated water	28	KLD

E.C. for Residential Township at Khasra no- 30,31,32,33,34,35,36,37ba, 37sa, 42,43,44,142, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 293sa, 293sa, 348, 354, 62,146 & 147, Village-Jatkhora, Pargana-Bhineur, Tehsil-Saraini Nagar, District- Lucknow, U.P., M/s Eldeco Housing & Industries Ltd.

<b>RAIN WATER HARVESTING</b>			
17	No of RWH of Pits Proposed	6	NOS
<b>PARKING</b>			
18	Total Proposed parking	283	Cars
<b>GREEN AREAS</b>			
19	Proposed Green Area (15%)	9376.02	SQM
<b>WASTE GENERATION</b>			
20	Municipal Solid Waste Generation	1.02	TPD
21	Quantity of Hazardous waste Generation	0.35	LTS/DAY
22	Quantity of Sludge Generation from STP	118	KG/DAY
<b>POWER</b>			
23	Total Power Requirement	1100 (Source : LIDA)	KW
24	DG set backup	535 KVA (250 KVA, 160 KVA (for Commercial) & 125 KVA (for club))	KVA

5. Population details:

RESIDENTIAL	TOTAL
Plotted	1500
EWS & LIG	64
TOTAL	1564
NON-RESIDENTIAL	
CLUB/COMMERCIAL (Employees etc)	
STAFF	438
TOTAL VISITORS	44
TOTAL POPULATION	2046

6. Water requirement details:

	POPULATION/ AREA/UNIT	RATE IN LTRS	TOTAL CITY IN KL
RESIDENTIAL			
DOMESTIC	1564	65	101.66
FLUSHING	1564	21	32.84
NON RESIDENTIAL (Working)			
DOMESTIC	438	15	6.57
FLUSHING	438	30	13.14
VISITORS			
DOMESTIC	44	5	0.22
FLUSHING	44	10	0.44
TOTAL POPULATION	2046		
GARDENING	9376.02	3.5	33
TOTAL WATER REQUIREMENT			138

Head	Source	Quantity
Fresh Water Requirement	Lucknow Industrial Development Authority	109 KLD
Treated Water Requirement	On site STP	79 KLD
> Estimated waste water Generation: 133 KLD > Waste water to be treated in onsite STP: 133 KLD > Additional waste water to be discharged into sewer: 28 KLD		



- Proposed treatment methodology : MBBR
- Proposed STP (Capacity): 160 KLD
- Treatment up to tertiary level.
- STP shall have power back-up for uninterrupted operation during power failure.
- Treated waste water will be used for flushing & gardening.

7. Solid waste details:

Waste Category	Quantity	Unit
Total Waste Generation	1.02	TPD
Organic Waste Generation	0.60	TPD
Sludge Generation	118	KG/Day
Hazardous Waste Generation (DG Waste Oil)	0.35	Ltrs/ Day

8. The project proposal falls under category-8(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee Meeting (SEAC) held on 15/05/2019 the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) in its Meeting held 11/06/2019 decided to grant the Environmental Clearance for proposed project along with subject to the effective implementation of the following general & specific conditions:-

**General Conditions:**

1. It shall be ensured that all standards related to ambient environmental quality and the emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
2. It shall be ensured that obtain the no objection certificate from the U P pollution control board before start of construction.
3. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started on the project or the activity without the prior environmental clearance.
4. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent Authority shall be obtained in this regards.
5. All trees felling in the project area shall be as permitted by the forest department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent Authority.
6. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
7. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
8. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.
9. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
10. Obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
11. Obtain necessary clearances from the competent Authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
12. Hazardous/Inflammable/Explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law, Necessary clearances in this regards shall be obtained.
13. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regards.
14. Suitable rainwater harvesting systems as per designs of groundwater department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
15. The emissions and effluents etc. from machines, instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
16. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
17. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.



18. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.
19. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
20. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
21. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
22. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
23. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
24. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as far as possible.
25. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.
26. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
27. Explore options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water, ground water etc.
28. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
29. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
30. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
31. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.
32. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
33. Prepare and present disaster management plan.
34. The project proponents shall ensure that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
35. A report on the energy conservation measures conforming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
36. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
37. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
38. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
39. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
40. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
41. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
42. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority.



43. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
44. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
45. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
46. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
47. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly and submitted with justification.
48. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where ever not possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
49. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken.
50. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
51. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
52. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.
53. The location of the STP should be such that it is away from human habitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
54. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
55. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
56. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North, South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
57. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
58. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.
59. E-Waste Management should be done as per MoEF guidelines.
60. Electrical waste should be segregated & disposed suitably as not to impose Environmental Risk.
61. The use of suitably processed plastic waste in the construction of roads should be considered.
62. Displaced persons shall be suitably rehabilitated as per prescribed norms.
63. Dispensary for first aid shall be provided.
64. Safe disposal arrangement of used toiletries items in Hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
65. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.
66. Ground Water downstream of Rain Water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination. Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.
67. The green belt shall consist of 50% trees, 25% shrubs and 25% grass as per MoEF norms.
68. A Separate electric meter shall be provided to monitor consumption of energy for the operation of sewage/effluent treatment in tanks.
69. An energy audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the authority.
70. Project proponents shall endeavor to obtain ISO: 14001 certification. All general and specific conditions mentioned under this environmental clearance should be included in the environmental manual to be prepared for the certification purposes and compliance.



71. Environmental Corporate Responsibility (ECR) plan along with budgetary provision amounting to 2% of total project cost shall be submitted (within the month) on need base assessment study in the study area. Income generating measures which can help in up-liftment of weaker section of society consistent with the traditional skills of the people identified. The program me can include activities such as old age homes, rain water harvesting provisions in nearby areas, development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. In addition, vocational training for individuals shall be imparted so that poor section of society can take up self employment and jobs. Separate budget for community development activities and income generating programmers shall be specified. Revised ECR plan is to be submitted within 3 month. Failing which, the environmental Clearance shall be deemed to be cancelled.
72. Appropriate safety measures should be made for accidental fire.
73. Smoke meters should be installed as warning measures for accidental fires.
74. Plan for safe disposal of R.O reject is to be submitted.

**Specific Conditions:**

1. The project proponent shall submit within the next 3 months the details of solar power plant and solar electrification details within the project.
2. The project proponent shall ensure to plant broad leave trees and their maintenance. The CPCB guidelines in this regard shall be followed.
3. The project proponent shall submit within the next 3 months the details on quantification of year wise CER activities along with cost and other details. CER activities must not be less 2% of the project cost. The CER activities should be related to mitigation of Environmental Pollution and awareness for the same.
4. The project proponent shall submit within the next 3 months the details of estimated construction waste generated during the construction period and its management plan.
5. The project proponent shall submit within the next 3 months the details of segregation plan of MSW.
6. The project proponent shall install the STP of adequate capacity for the treatment of entire sewage generated and ensure that waste water is properly treated in STP at and maximum reused for gardening, flushing system etc. For reuse of treated waste water for irrigation sprinkler and drip irrigation system shall be installed and maintained for proper function. Part of the treated sewage, if discharged to sewer line, shall meet the prescribed standards for the discharge. Under any circumstances untreated sewage shall not be reused/recycle or discharged to municipal sewer line.
7. The project proponent will ensure that proper dust control arrangements are made during construction and proper display board is installed at the site to inform the public the steps taken to control air pollution as per the Construction and Demolition Waste Management Rules.
8. The project proponent shall install micro solar power plants, toilets in nearby villages, public place or school from CER fund of the project for which E.C is granted in addition to and water harvesting pits and carbon sequestration parks / designed ecosystems.
9. Solar energy to be used alternatives on the road and common places for illumination to save conventional energy as per ECBC Code.
10. The project proponent shall submit within the next 3 month the data of ground water quality including fluoride parameter to the limit of minimum deduction level for all six monitoring stations.
11. 15% area of the total plot area shall be compulsorily made available for the green area development including the peripheral green area. Plantation of trees should be of indigenous species and may be as per the consultation of local district Forest Officer.
12. The waste water generated should be treated properly in scientific manner i.e. domestic waste water to be treated in STP and effluent such as RO rejects with high TDS and other chemical bearing effluent shall be treated separately.
13. Permission from local authority should be taken regarding discharge of excess water into the sewer line.
14. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FAR norms of the competent authority & it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work. Plan approving authority should also ensure the zoning permissibility for the proposed project as per the approved development plan of the area.
15. "Consent for Establishment" shall be obtained from UP Pollution Control Board.



16. All required sanitary and hygienic measures should be in place before starting construction activities and to be maintained throughout the construction phase.
17. Project proponent shall ensure completion of STP, MSW disposal facility, green area development prior to occupation of the buildings.
18. Municipal solid waste shall be disposed/managed as per Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2016.
19. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as cylinder for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche and First Aid Room etc.
20. Adequate drinking water and sanitary facilities should be provided for construction workers at the site. Provision should be made for mobile toilets. The safe disposal of wastewater and solid wastes generated during the construction phase should be ensured.
21. The solid waste generated should be properly collected and segregated. Dry/inert solid waste should be disposed off to the approved sites for land filling after recovering recyclable material.
22. Corporate Environmental Responsibility (CER) shall be prepared by the project proponent and the details of the various heads of expenditure to be submitted as per the guidelines provided in the recent CER notification No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018. A copy of resolution of board of directors shall be submitted to the authority. A list of beneficiaries with their mobile nos./address should be submitted along with six monthly compliance reports.
23. No parking shall be allowed outside the project boundary.
24. Digging of basement shall be undertaken in view of structural safety of adjacent buildings under information/consultation with District Administration/Mining Department. All the topsoil excavated during construction activities should be stored for use in horticulture /landscape development within the project site. Additional soil for leveling of the proposed site shall be generated within the sites (to the extent possible) so that natural drainage system of the area is protected and improved.
25. Surface rain water has to be collected in kacchha pond for ground water recharging and irrigation of horticulture and peripheral plantation.
26. The approval of competent authority shall be obtained for structural safety of the buildings due to any possible earthquake, adequacy of fire fighting equipments etc. as per National Building Code including measures from lighting.
27. Disposal of muck during construction phase should not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed off taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
28. Any hazardous waste generated during construction phase should be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the UP Pollution Control Board.
29. The diesel generator sets to be used during construction phase should be low sulphur diesel type and should conform to Environments (Protection) Rules prescribed for air and noise emission standards.
30. Ambient noise levels should conform to residential standards both during day and night. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality should be closely monitored during construction phase. Adequate measures should be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/UPPCB.
31. The green area design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential area. The open spaces inside the plot should be landscaped and covered with grass and shrubs. Green area Development shall be carried out considering CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/ Agriculture Dept.
32. The building should have adequate distance between them to allow movement of fresh air and passage of natural light, air and ventilation.
33. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Construction of pavements around trees should be able to facilitate suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
34. Ready Mix Concrete and Sprinkler to be used for curing and quenching during construction phase.
35. Roof top water in rainy season is to be discharged into RWH pits for ground water recharging. Arrangement shall be made that waste water and storm water do not get mixed.



36. NOC from Ground Water Board is to be submitted for drilling of tube well for use of Water Supply.

37. All the Internal drains are to be covered till the disposal point.

38. This environmental clearance is issued subject to land use verification. Local authority / planning authority should ensure this with respect to Rules, Regulations, Notifications, Government Resolutions, Circulars, etc. issued if any.

39. Reflecting paint should be used on the roof top and side walls of the building tower for cooling effect.

Concealing factual data and information or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions stipulated in the Prior Environmental Clearance attract action under the provision of Environmental (Protection) Act, 1986.

This Environmental Clearance is subject to ownership of the site by the project proponents in confirmation with approved Master Plan for Lucknow in case of violation; it would not be effective and would automatically be stand cancelled.

The project proponent has to ensure that the proposed site is not a part of any no- development zone as required/prescribed/identified under law. In case of the violation this permission shall automatically deemed to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this Clearance shall automatically deemed to be cancelled.

The project proponent has to mandatorily submit the compliance of specific conditions no- 1, 3, 4 & 5 given in E.C. letter within 3 months, failing which the Clearance shall automatically deemed to be cancelled.

Further project proponent has to submit the regular 6 monthly compliance report regarding general & specific conditions as specified in the E.C. letter and comply the provision of EIA notification 2006 (as Amended).

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.



(Ashish Tiwari)

Member Secretary, SEIAA

No..... /Parya/SEAC/4763/2019 Dated: As above

Copy with enclosure for information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Department of Environment, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Advisor, IA Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi.
3. Additional Director, Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. District Magistrate Lucknow.
5. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
6. Copy to Web Master/ guard file.

(Ashish Tiwari)

Member Secretary, SEIAA



# GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)

Ministry of Jal Shakti

Government of Uttar Pradesh

## Form 8 (C)

[See Rule 8(1)]

### AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO: NOC014175

VALID FROM 06/11/2023 TO 05/11/2028

{UIS10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

<b>Registration No.: 202309000489</b>			
<b>Name of the Owner</b>	SHAILESH SHUKLA		
<b>Designation</b> पद	Asst Manager	<b>Company Name</b> कंपनी का नाम	M/s ELDECO HOUSING AND INDUSTRIES LIMITED
<b>Company Address</b> कंपनी का पता	Eldeco Corporate Chamber -I 2nd floor Gomti Nagar	<b>Authorization Letter</b> प्राधिकार पत्र	Download
<b>Address of the Applicant</b>	ELDECO CORPORATE CHAMBER 1, 2ND FLOOR, OPP. MANDI PARISHAD VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW	<b>Application No.</b>	LKNW0923NIF0096
<b>Date of Submission</b>	14/09/2023	<b>Specimen Signature</b>	
<b>Location Particulars</b>			
<b>District</b>	Lucknow	<b>Block</b>	SAROJINI NAGAR
<b>Plot No./Khasra No.</b>	"Eldeco Imperia" Khasra No. 140	<b>Municipality/Corporation</b>	No
<b>Ward No./Holding No.</b>			Jaitikhera, Sisandi Road, Lucknow
<b>Particular of the Proposed Well and Pumping Device</b>			
<b>Date of Construction/Sinking of the Well</b>	30/12/2023		
<b>Type of Well</b>	Tube Well/Boring	<b>Depth of the Well (In meter)</b>	100.00
<b>Purpose of well</b>	Infrastructural	<b>Assembly Size(For Tube Well)</b>	
<b>Strainer Position (For Tube Well)</b>			
<b>Type of Pump Used</b>	Submersible	<b>H.P. of the Pump</b>	10.00
<b>Operational Device</b>	Electric Motor	<b>Rate of Withdrawal (m<sup>3</sup>/hr.)</b>	25.00
<b>Date of Energization (In Case of Electric Pump)</b>		30/12/2023	
<b>Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m<sup>3</sup>/hr.):</b>	25.00	<b>Maximum Allowable Running Hours Per Day:</b>	5.20

<b>Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:</b>	47450.00	<b>Recharge Required</b>	23725.00
---	----------	--------------------------	----------

- This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at Sl. (3j), for Running Hours per day as shown at Sl. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at Sl. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.
- Holder of this NOC is hereby directed to assure annual recharge of 23725.00 cubic meter, as specified under the application form within the given time period.

### GENERAL CONDITIONS:

- Holder of this NOC is hereby directed to fill from 1(A) for registering his/her well within 90 days as mentioned in application form shall only started after registration of his/her NOC.
- In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- All Users abstracting ground water in excess of 100 m<sup>3</sup>/d shall be required to submit impact assessment report prepared by an accredited consultant from CGWA and National Accreditation Board for Education and Training (NABET). The report should highlight environmental risks and proposed management strategies to overcome any significant environmental issues such as ground water level decline, land subsidence etc. within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. The list of accredited Individuals/ Institutions is available on the official web-portal of CGWA.
- For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix digital water flow meters (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well shall not exceed to the recorded rate from water meters
- The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands
- In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration
- In case, any of the particulars / information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.
- The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.
- Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis

#### Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing when ever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- No. of piezometers to be constructed & Type of water level monitoring mechanism shall be as per below table:

S.No	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No.of piezometers required	Monitiring Mechanism	
			Manual	DWLR with Telemetry
1	< 10	0	0	0
2	11 - 50	1	1	0
3	50- 500	1	0	1
4	> 500	2	0	2

- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.

- o Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.
- Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.
- 
- **SPECIFIC CONDITIONS:**
- **(A) For Industrial User:** No Objection Certificate for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:
  - i) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
  - ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependence on ground water resources.
  - iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m<sup>3</sup>/d shall be required to undertake annual water audit through Confederation of Indian Industries (CII)/ Federation Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)/ National Productivity Council (NPC)/ PHD Chamber of Commerce & Industries / Laghu Udyog Bharati certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next five years through appropriate means.
  - iv) Construction of observation well(s) (piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in General Condition no.10 shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10 m<sup>3</sup> /day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent. The piezometer (observation well) shall be constructed at a minimum distance of 50 m from the bore well/production well. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/ wells. Monthly water level data shall be submitted online to the Ground Water Department, UP.
  - v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughter house, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry.
  - vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
  - vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
- 
- **(B) Infrastructural User:** The No Objection Certificate for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions:
  - i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regular monitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data online to Ground Water Department, UP as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by District Ground Water Management Council.
  - ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m<sup>3</sup> /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc

Date :**28/11/2023**

Place:**Lucknow**

**This certificate is electronically generated and does not require digital signature**



# GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)

Ministry of Jal Shakti

Government of Uttar Pradesh

## Form 8 (C)

[See Rule 8(1)]

### AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO: NOC025557

VALID FROM 06/11/2023 TO 05/11/2028

{UIS10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

<b>Registration No.: 202309000488</b>			
<b>Name of the Owner</b>	SHAILESH SHUKLA		
<b>Designation</b> पद	Asst Manager	<b>Company Name</b> कंपनी का नाम	M/s ELDECO HOUSING AND INDUSTRIES LIMITED
<b>Company Address</b> कंपनी का पता	Eldeco Corporate Chamber -I 2nd floor Gomti Nagar	<b>Authorization Letter</b> प्राधिकार पत्र	Download
<b>Address of the Applicant</b>	ELDECO CORPORATE CHAMBER 1, 2ND FLOOR, OPP. MANDI PARISHAD VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW	<b>Application No.</b>	LKNW0923NIF0095
<b>Date of Submission</b>	14/09/2023	<b>Specimen Signature</b>	
<b>Location Particulars</b>			
<b>District</b>	Lucknow	<b>Block</b>	SAROJINI NAGAR
<b>Plot No./Khasra No.</b>	"Eldeco Imperia" Khasra no. 140	<b>Municipality/Corporation</b>	No
<b>Ward No./Holding No.</b>			Jaitikhera, Sisandi Road, Lucknow UP
<b>Particular of the Proposed Well and Pumping Device</b>			
<b>Date of Construction/Sinking of the Well</b>	20/12/2023		
<b>Type of Well</b>	Tube Well/Boring	<b>Depth of the Well (In meter)</b>	100.00
<b>Purpose of well</b>	Infrastructural	<b>Assembly Size(For Tube Well)</b>	
<b>Strainer Position (For Tube Well)</b>			
<b>Type of Pump Used</b>	Submersible	<b>H.P. of the Pump</b>	10.00
<b>Operational Device</b>	Electric Motor	<b>Rate of Withdrawal (m<sup>3</sup>/hr.)</b>	25.00
<b>Date of Energization (In Case of Electric Pump)</b>		20/12/2023	
<b>Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m<sup>3</sup>/hr.):</b>	25.00	<b>Maximum Allowable Running Hours Per Day:</b>	5.20

<b>Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:</b>	47450.00	<b>Recharge Required</b>	23725.00
---	----------	--------------------------	----------

- This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at Sl. (3j), for Running Hours per day as shown at Sl. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at Sl. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.
- Holder of this NOC is hereby directed to assure annual recharge of 23725.00 cubic meter, as specified under the application form within the given time period.

### GENERAL CONDITIONS:

- Holder of this NOC is hereby directed to fill from 1(A) for registering his/her well within 90 days as mentioned in application form shall only started after registration of his/her NOC.
- In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- All Users abstracting ground water in excess of 100 m<sup>3</sup>/d shall be required to submit impact assessment report prepared by an accredited consultant from CGWA and National Accreditation Board for Education and Training (NABET). The report should highlight environmental risks and proposed management strategies to overcome any significant environmental issues such as ground water level decline, land subsidence etc. within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. The list of accredited Individuals/ Institutions is available on the official web-portal of CGWA.
- For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix digital water flow meters (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well shall not exceed to the recorded rate from water meters
- The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands
- In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration
- In case, any of the particulars / information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.
- The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.
- Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis

#### Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing when ever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- No. of piezometers to be constructed & Type of water level monitoring mechanism shall be as per below table:

S.No	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No.of piezometers required	Monitiring Mechanism	
			Manual	DWLR with Telemetry
1	< 10	0	0	0
2	11 - 50	1	1	0
3	50- 500	1	0	1
4	> 500	2	0	2

- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.

- o Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.
- Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.
- 
- **SPECIFIC CONDITIONS:**
- **(A) For Industrial User:** No Objection Certificate for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:
  - i) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
  - ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependence on ground water resources.
  - iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m<sup>3</sup>/d shall be required to undertake annual water audit through Confederation of Indian Industries (CII)/ Federation Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)/ National Productivity Council (NPC)/ PHD Chamber of Commerce & Industries / Laghu Udyog Bharati certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next five years through appropriate means.
  - iv) Construction of observation well(s) (piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in General Condition no.10 shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10 m<sup>3</sup> /day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent. The piezometer (observation well) shall be constructed at a minimum distance of 50 m from the bore well/production well. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/ wells. Monthly water level data shall be submitted online to the Ground Water Department, UP.
  - v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughter house, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry.
  - vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
  - vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
- 
- **(B) Infrastructural User:** The No Objection Certificate for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions:
  - i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regular monitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data online to Ground Water Department, UP as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by District Ground Water Management Council.
  - ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m<sup>3</sup> /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc

Date :**28/11/2023**

Place:**Lucknow**

**This certificate is electronically generated and does not require digital signature**